डाक पंजीयन सं. आर.जे./जे.पी.सी./मन्थली–08/2010–12 RNI - 65127/94

सहकार समाचार बुलेटिन

वर्ष : 16 अंक : 11 वार्षिक :100 रु एक प्रति : 10 रु जुलाई, 2010

सहकारिता आंदोलन आर्थिक विकास का जरिया –मुख्यमंत्री श्री गहलोत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में सहकारी आंदोलन को आर्थिक विकास का जरिया बताया है। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को प्रभावी बनाने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत की और से 88 वें अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं 16 वें संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस पर जारी संदेश में कहा कि सहकारिता आंदोलन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है।

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि आमजन को बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहकारिता की प्रमुख भूमिका रही है। श्री मीणा ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार ने जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कर संचालन की जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपी हैं।

श्री मीणा ने कहा कि इस वर्ष सहकारिता दिवस का आधार बिन्दु ''सहकारी उपक्रमों से महिला सशक्तिकरण'' रखा जाना इस बात का प्रतीक है कि सहकारिता से ही महिला सशक्तिकरण संभव है।

सहकारिता राज्यमंत्री श्री बृजेन्द्र ओला ने सहकारी आंदोलन को महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की करते हुए युवाओं व महिलाओं को सहकारिता से जोड़ने पर बल दिया।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना को आधार नहीं मिल सकता।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सहकारी संस्थाएं 18 हजार करोड़ की कार्यशील पूंजी से आर्थिक विकास को नई दिशा दे रही है।

अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर ऋण वितरण

संदेश

मुख्य मंत्री
राजस्थान

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 3 जुलाई, 2010 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 'सहकारी उपक्रमों से महिला सशक्तिकरण' विषय पर 16 वें संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

'एक सबके लिए–सब एक के लिए' मूलमंत्र पर आधारित हमारे देश का सहकारिता आन्दोलन दुनिया में सबसे बड़ा है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने देश के योजनाबद्ध विकास में सहकारिता को महत्व दिया। उसी का परिणाम है कि इस आन्दोलन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि, पशुपालन एवं डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। दुनिया के विकासशील देशों में सहकारिता आज आवश्यकता है। अल्पविकसित देश तेजी से आर्थिक विकास के लिये सहकारिता को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं।

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण जरिया है। इस साल किसानों को पांच हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण के साथ ही खरीफ में पिछले वर्ष से डेढ़ गुणा से अधिक ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन निरन्तर मजबूत हो रहा है।

आशा है आने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के कार्यक्रम प्रदेश और देश में सहकारी आन्दोलन को और अधिक व्यापक बनाने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण होंगे।

मैं इस शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के आव्हान बिन्दु के अनुरूप महिला स्वयं सहायता समूह की तरह सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय भागीदारी की अपील करता हूं और इस दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की सफलता के लिये शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(अशोक गहलोत)

परसादीलाल मीणा
मंत्री
सहकारिता, ...
राजस्थान सरकार

कमरा नं. 3131, मुख्य भवन
शासन सचिवालय-जयपुर-302005
फोन: 0141-2227418 (कार्या.)
0141-2220011 (निवास)

दिनांक: ....

संदेश

आगामी 3 जुलाई को आयोजित 88 वें अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं 16 वें यूनाइटेड नेशन्स के इंटरनेशनल डे ऑफ को-ऑपरेटिव्स के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण में सहकारिता की सकारात्मक भूमिका को देखते हुए इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एलायंस ने इस वर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आव्हान बिन्दु "सहकारी उपक्रमों से महिला सशक्तिकरण" (Cooperative Enterprise Empowers Women) रखा है।

सहकारिता हमारे जीवन से रची-बसी व्यवस्था है। किसानों के जीवन में ... आर्थिक विकास की धारा से जोड़ने में सहकारिता की मुख्य भूमिका रही है। राज्य में सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करते हुए ... सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी चुने हुए संचालकों को सौंपने के साथ ही उन्हें अधिकार संपन्न बनाया गया है। सहकारी ऋण सुविधा के विस्तार के साथ ही ऋण वितरण का सरलीकरण किया गया है। ... सहकारी समितियों को ग्रामीणों के आर्थिक विकास की मुख्य केन्द्र बनाते हुए उन्हें आर्थिक रूप से ... विकसित किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ के ऋण वितरण के साथ ही ... ऋण वितरण करने का निर्णय लिया गया है।

सहकारिता से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों व सहकार कर्मियों से मेरा आग्रह है कि प्रदेश के सहकारी आंदोलन को देश का अग्रणी सहकारी आंदोलन बनाने के सार्थक प्रयासों में सहयोग करते हुए सहकारी सुविधाओं के उचित संचालन और आंदोलन को जनोन्मुखी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

मैं, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर समूचे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सफलता की कामना करता हूं।

जय सहकार!

(परसादीलाल मीणा)
सहकारिता मंत्री

Media/DO_Letter_Minister

संदेश

(...)

संदेश

संदेश

खरीफ में रेकार्ड 4500 करोड़ के लिए फसली सहकारी ऋण वितरण का कार्यक्रम

किसानों को 15 जुलाई तक खरीफ के लिए सहकारी ऋण उपलब्ध कराएं

इस वर्ष खरीफ में काश्तकारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 4500 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाएंगे। यह गत वर्ष की तुलना में दोगुने होने के साथ ही किसी एक वर्ष में सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों को वितरित फसली सहकारी ऋणों में सर्वाधिक होंगे।

सचिवालय में सहकारिता विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा और रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों व सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से रू-ब-रू होते हुए दी। श्री मीणा ने बताया कि अब तक बैंकों द्वारा लगभग एक हजार करोड़ रुपए के फसली सहकारी कर्जे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने सहकारी बैंकों को निर्देश दिये कि वर्षा का दौर शुरू हो गया है और काश्तकारों को नई फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक रूप से 15 जुलाई तक सहकारी कर्जेउपलब्ध कराएं।

प्रमुख शासन सचिव श्री मीणा ने कहा कि इस वर्ष सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से नए काश्तकारों, ऋण माफी व ऋण राहत योजना के लाभार्थी काश्तकारों को भी सहकारी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आदान अनुदान काश्तकारों को वितरित करने के साथ ही काश्तकारों को समझाइश से सदस्य बनाकर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन भी करवाया जा सकता है।

श्री मीणा ने कहा कि अवधिपार सहकारी ऋणों के दोषी ऋणियों को 30 जून तक ऋण राहत योजना का लाभ दिया जा सकता है। राहत योजना में 75 प्रतिशत राशि जमा करवाकर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त नहीं करने वाले ऋणियों से सख्ती से वसूली की तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि 30 जून तक ऐसे जानबूझ कर ऋण जमा नहीं कराने वाले ऋणियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की बकाया स्क्रीनिंग को एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए ताकि व्यवस्थापकों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही शुरु की जा सके। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों व भूमि विकास बैंकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि विभाग को अन्यथा स्थिति में सहकारिता अधिनियम के तहत अप्रिय कदम उठाने को बाध्य होना पड़ेगा।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत अन्तर की राशि जिला स्तर से प्राप्त करने और परिवहन के अन्तर की राशि की मांग जिला रसद अधिकारी के माध्यम से भिजवाने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर एक सौ नए उपहार मिनी सुपर मार्केट खोले जाने हैं। स्वयं सहायता समूहों को कम वित्त पोषण को गंभीरता से लेते हुए श्री शर्मा ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कड़ी बन्धन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सोयाबीन के बीज की कोई कमी नहीं है और तिलम संघ से भी बीज प्राप्त कर किसानों को दिए जा सकते हैं।

राजफैड के प्रबन्ध संचालक श्री विकास सीताराम जी भाले ने बताया कि राजफैड द्वारा बीज निगम से समन्वय बनाते हुए खरीफ बीजों की उपलब्धता बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आन्ध्र प्रदेश से बाजरे के बीज मंगाए जा रहे हैं।

बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वय सुश्री लक्ष्मी बैरवा, श्री सोमदत्त, प्रबन्ध संचालकों में अपेक्स बैंक के श्री आर.सी.एस.जोधा, राज्य भूमि विकास बैंक के श्री आर.सी.शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग श्री हनुमान सिंह, श्री रामजी लाल सोनी, महाप्रबन्धक उपभोक्ता संघ श्री मुकुन्द सिंह ने भी हिस्सा लिया।

सहकारिता विभाग में आयोजित विदाई समारोह में अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री आर.सी. शर्मा एवं कार्यालय सहायक श्रीमती निर्मला वर्मा को सेवानिवृति पर भावविनी विदाई दी गई।

राज्य स्तरीय समारोह

महिला स्वयं सहायता समूहों को अब 6 प्रतिशत अनुदानित दर पर वित्तपोषण

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने घोषणा की है कि राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों को अब 6 प्रतिशत की अनुदानित ब्याज दर पर वित्तपोषण किया जाएगा। उन्होंने सहकारी बैंकों के संचालक मण्डलों से भी आग्रह किया कि वे स्वयं सहायता समूहों को निजी कोष से 11 प्रतिशत की दर पर वित्तपोषण करें ताकि 6 प्रतिशत अनुदान के बाद इन्हें यह ऋण केवल 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा सके।

श्री मीणा 3 जुलाई को 88वें अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं 16वें यूएन डे ऑफ कोऑपरेटिव्ज पर राइसम द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री मीणा एवं रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक की और से 14 महिला स्वयं सहायता समूहों को 50-50 हजार रुपए के ऋण के चैक दिए। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला सहकारी समितियों के उत्पादों को सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से विपणन सुविधा उपलब्ध कराने का भी आश्वासन देते हुए महिलाओं से आग्रह किया कि समूहों द्वारा तैयार उत्पाद् गुणवत्तायुक्त होने चाहिए क्योंकि गुणवत्ता ही सहकारिता की विश्वसनीयता और पहचान है।

श्री मीणा ने कहा कि इस साल सहकारी बैंकों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी आधार पर कार्य करने से ज्ञान में वृद्धि, आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी और बेहतर कार्य परिणाम तथा महिलाओं का मनोबल बढ़ सकेगा।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने इस अवसर पर जिला स्तर पर महिलाओं के सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलने की घोषणा करते हुए अब तक जिला स्तर पर महिला भण्डार खोलने की पाबंदी हटाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी शाश्वत परंपरा में महिलाओं को उच्च दर्जा प्राप्त है, ज्ञान, धन और शक्ति की अधिष्ठात्री देवियां ही है।

श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में राजस्थान ही ऐसा पहला प्रदेश होगा जहां रिद्धी-सिद्धी योजना में 500 महिला सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् उपभोक्ता सामग्री के वितरण के साथ ही खाद-बीज वितरण तक का काम दिया गया है। वित्तीय सहायता दी गई है। इसलिए इन महिलाओं समितियों को भी चुनौती के रुप में काम करते हुए बेहतर कार्य परिणाम देने होंगे।

राइसम के निदेशक श्री आर.के. पुरी ने स्वागत करते हुए बताया कि सहकारिता से ही महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को आसानी से पूरा किया जा सकता है। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती शोभा कौशिक ने बताया कि 400 मिड डे मिल केन्द्र और 1100 आंगनबाड़ी केन्द्रों का महिला समितियों द्वारा सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है।महिला स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधि श्रीमती किरण व पूजा ने आसान ब्याज दर पर ऋण दिलाने और विपणन सहयोग पर जोर दिया।

राइसम के अतिरिक्त निदेशक श्री अशोक जोशी ने बताया कि 80 करोड़ सदस्यों से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन सहकारिता आंदोलन है। संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर भी सहकारिता से ही उपलब्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री सोमदत्त, विभाग व संस्थाओं के अधिकारी व बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।

राजफैड को इफको द्वारा एक करोड़ रुपए का लाभांश

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ राजफैड को इफको की और से एक करोड़ रुपए का लाभांश चैक दिया गया।

सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा एवं प्रबंध संचालक राजफैड श्री विकास एस. भाले को इफको के वरिष्ठ प्रबन्धक वित्त श्री एस.एम. पेडिवाल एवं प्रबंधक विपणन श्री सोहन लाल जैन ने इफको की और से राजफैड के हिस्से का एक करोड़ रुपए का लाभांश चैक भेंट किया।

इस मौके पर राजफैड के महाप्रबंधको में सर्वश्री वाई.के. शर्मा, हरिओम पिपलानी, अमित शर्मा एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री सुधीर कुमार बोहरा भी उपस्थित थे।

सहकारिता विभाग से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, आदेश, निर्देश, परिपत्र, स्थानान्तरण, गतिविधियां, प्रकाशन, सहकार समाचार बुलेटिन के लिए लॉग ऑन करे-
www.rajcooperatives.nic.in

जयपुर में खुलेंगे नए सहकार दवा बिक्री केन्द्र, सहकारी सुविधाओं का होगा विस्तार

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा जयपुर में 3 जनौषधि केन्द्र सहित झालाणा डूंगरी, तूंगा व बगरू में नए सहकारी केन्द्र खोले जाएंगे, वहीं सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चरक एवं धन्वन्तरी तथा मानस आरोग्य सदन मानसरोवर व गणगौरी बाजार सेटेलाईट अस्पताल में नए सहकारी दवा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए स्थान आवंटित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सहकारी रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने सहकारी उपभोक्ता संघ के कार्यो की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संघ की निकट भविष्य में जयपुर व आसपास में 100 सहकारी दवा बिक्री केन्द्र शुरू करने की कार्य योजना है, जबकि इस समय 77 सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल इम्प्लान्ट्स्, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सर्जरी किट व ऑर्थोपेडिक आइटम्स भी सीधे उत्पादक कम्पनियों से प्राप्त कर मरीजों को उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि सस्ती दरों पर यह आइटम प्राप्त होने से मरीजों का सस्ता ईलाज हो सके। जनौषधि केन्द्रों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर के कांवटिया अस्पताल सहित राज्य में 33 जनौषधि केन्द्र आरंभ कर दिए गए हैं, 7 लाइसेंस प्राप्त होते ही शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार 9 जनौषधि केन्द्रों के लिए स्थान प्राप्त हो गया है और निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

श्री शर्मा ने कहा कि सहकारी दवा बिक्री केन्द्रों से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने के साथ विक्रेताओं की बिक्री प्रोत्साहन योजना को एन.ए.सी. के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ को चिकित्सकों से समन्वय बनाते हुए सहकारी दवा बिक्री केन्द्रों पर मांग के अनुसार दवा उपलब्ध करावें, ताकि अनुपलब्धता की स्थिति नहीं आ सके। उन्होंने आर डी पी एल द्वारा केवल 80 जैनेरिक दवांए ही उपलब्ध कराने पर असंतोष व्यक्त करते हुए बेहतर तालमेल बनाते हुए जनौषधि केन्द्रों पर आवश्यकता की सभी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने कहा कि आम नागरिकों को उचित मूल्य पर आम जरुरत की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जयपुर शहर में नए उपहार सुपर मार्केट खोलें। फ्रेंचाइजी आधार पर भी उपहार सुपर मार्केट खोलने की संभावनाएं तलाशी जा सकती है।

उपभोक्ता संघ के प्रबन्ध संचालक श्री आर.एस.जाखड़ ने कम्प्यूटर स्लाईड शो के माध्यम से उपभोक्ता संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर शहर में 8 उपहार सुपर मार्केट के माध्यम से रोजमर्रा की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उपभोक्ता संघ का100 करोड़ रुपए की उपभोक्ता सामग्री व दवाएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। गत वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया था। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री सोमदत्त, उप रजिस्ट्रार उपभोक्ता श्रीमती उषा कपूर, महाप्रबन्धक श्री मुकुन्द सिंह, प्रबन्धकों में श्री योगेन्द्र शर्मा-मेडिकल, राजेन्द्र शेखावत-मार्केटिंग, राजेन्द्र शर्मा-सिविल सप्लाई व उपभोक्ता संघ के वित्त अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष करने के लिए संचालक मण्डल अधिकृत-सहकारिता मंत्री

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की अधिवार्षिक आयु 58 से 60 वर्ष करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालक मण्डल को अधिकृत कर दिया गया है।

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि व्यवस्थापकों द्वारा लंबे समय से सेवानिवृत की आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्री स्तर से पिछले दिनों भूमि विकास बैंकों के चयनित अध्यक्षों, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा एवं रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा की उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों में भी सहकारी संस्थाओं को इस तरह के निर्णय समिति के संचालक मण्डल स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। राज्य सरकार ने वैद्यनाथन पैकेज के तहत सहकारिता कानून में किए गए संशोधन के अनुसार आगे बढ़ते हुए अब ग्राम सेवा सहकारी समिति को अधिकृत कर दिया है कि वे व्यवस्थापकों की सेवानिवृति अपने स्तर से संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय कर 58 से 60 वर्ष कर सकते हैं।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने बताया कि राज्य में पांच हजार से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत है। पिछले माह ही राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर आवेदन प्राप्त कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों की स्क्रीनिंग से सेवाएं नियमित कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को बड़ी राहत दी है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु 58 से 60 वर्ष करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित सहकारी समिति अपने संचालक मण्डल की बैठक आयोजित कर आदेशों का प्रस्ताव लेकर इन्हें लागू करने को अधिकृत होगी।

8 जिलों के लघु-सीमान्त किसानों को बाजरा बीजों के मिनीकिटों का 11जून से नि:शुल्क वितरण -सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया है कि राज्य के 8 जिलों के लघु एवं सीमान्त किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से बाजरा बीज के मिनीकिटों का नि:शुल्क वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि यह कृषि विभाग, राज्य बीज निगम, राजफैड व सहकारिता विभाग का समन्वित कार्यक्रम था। इससे प्रमुख बाजरा उत्पादक आठों जिलों के छोटे किसानों को उन्नत बाजरा बीज मुफ्त में दिया गया।

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि मिनीकिटों का वितरण बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जालौर, सीकर, झुन्झुनूं, चुरु एवं बीकानेर के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि बीज राज्य बीज निगम से उपलब्ध कराये गए और इनके वितरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया।

रजिस्ट्रार ने दी मोबाईल संदेश से काश्तकारों को जानकारी

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने राजस्थान सहकारी इफको किसान संचार योजना के तहत् काश्तकारों को वाचिक मोबाईल संदेश के माध्यम से 8 जिलों में बाजरा बीजों के नि:शुल्क वितरण की जानकारी देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के काश्तकारों से ग्राम सेवा सहकारी समिति से खरीफ के लिए फसली सहकारी ऋण प्राप्त करने का आग्रह किया है।

उन्होंने मोबाईल संदेश जारी करते हुए बताया कि राजफैड ने बीज निगम से समन्वय बनाते हुए 15 हजार 168 क्विंटल बाजरा के मिनीकिट क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्तर पर उपलब्ध करा दिए हैं। इसमें से 14 हजार 70 क्विंटल बाजरा बीज के मिनीकिट ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 8 जिलों बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जालौर, सीकर, झुन्झुनं ,चूरु एवं बीकानेर के 12 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 17 हजार 600 क्विंटल बाजरा बीज के मिनीकिटों का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।

राजस्थान सहकार इफको किसान संचार के राज्य प्रभारी श्री हंसराज सहारण ने बताया कि राजस्थान सहकार किसान संचार योजना काश्तकारों के लिए वरदान सिद्ध होने लगी है। सहकारिता द्वारा शुरु की गई इस योजना में ग्रामीणें व काश्तकारों को पांच नि:शुल्क वाचिक संदेश जारी कर खेती-बाड़ी, बागवानी, पशुपालन, पशुओं की बीमारी, मण्डी के भाव एवं मौसम आदि की जानकारी दी जाती है। इस अवसर पर इफको संचार के मैनेजर श्री एस.के. कटारिया व श्री उमेश कुमार भी उपस्थित थे।

राजफैड नोडल संस्था

राजफैड के प्रबंध संचालक श्री विकास एस.भाले ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाजरा बीज प्रतिस्थापना दर **एसआरआर** व उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से बाजरा बीज के मिनीकिटों का वितरण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान बीज निगम द्वारा संकर किस्म के 1.5 किग्रा. के बाजरा बीजों के मिनीकिट मय पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज **पीओपी** ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उपलब्ध कराए हैं।

चुरु केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक श्री नेतराम यादव ने रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा को बैंक के लाभांश का चैक भेंट किया। इस अवसर पर बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री एस.डी. चारण भी उपस्थित थे।

जैनेरिक दवाएं नहीं लिखने वाले चिकित्सकों पर कार्यवाही होगी

आरडीपीएल दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें–प्रमुख सचिव सहकारिता

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने कहा है कि जैनेरिक दवाएं नहीं लिखने वाले चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने राजस्थान ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल लि.(आरडीपीएल) से भी जनोषधि केन्द्रों पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

श्री मीणा सचिवालय में जनोषधि केन्दों की प्रगति, दवाओं की उपलब्धता और दुकानों के आवंटन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमनागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। चिकित्सकों द्वारा जनोषधि केन्द्र में उपलब्ध जैनेरिक दवाएं नहीं लिखने और आरडीपीएल द्वारा दवाओं की उपलब्धता समय पर नहीं बनाये रखने से आमनागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री मीणा ने जयपुरिया अस्पताल में 30 में से केवल दो चिकित्सकों द्वारा ही जैनेरिक दवाएं लिखने व कांवटिया अस्पताल में भी जैनेरिक दवाएं नहीं लिखने की प्रवृत्ति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से 15 दिन में एक बार व दोनों अस्पतालों के प्रभारियों से चिकित्सकों द्वारा जैनेरिक दवाएं लिखने की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद गरीब व आमनागरिकों के हित में सरकार की सस्ता ईलाज मुहेया कराने की मंशा पर जैनेरिक दवाएं नहीं लिखने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

श्री मीणा ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय सहित मेडिकल कॉलेजों वाले चिकित्सालयों में जनोषधि केन्द्र शुरु करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने पर जोर दिया। स्थान के अभाव में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जनोषधि केन्द्र अभी तक आरंभ नहीं हो पाया है। उन्होंने चिकित्सालयों में कार्यरत मेडिकल रिलिफ सोसायटी में बीपीएल एवं एपीएल मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली दवाएं जनोषधि केन्द्र से खरीदने को कहा और स्पष्ट किया कि जनोषधि केन्द्र की दवाएं अन्य स्थान से खरीद से मंहगी नहीं होगी।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि सहकारिता द्वारा 36 जनोषधि केन्द्र शुरु कर दिए हैं और चार स्थानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में है। आरडीपीएल द्वारा अभी 70–75 दवाओं की आपूर्ति करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पूरी दवाएं समय पर प्राप्त नहीं होगी तब तक जनोषधि केन्द्रों का लाभ आम आदमी को प्राप्त नहीं हो सकेगा।

श्री शर्मा ने कहा कि आरडीपीएल को दवाओं की आपूर्ति करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि दवाओं की एक्सपायरी पास की न हो। उन्होंने उपभोक्ता संघ व उपभोक्ता भण्डारों को भी निर्देश दिए कि दवाओं की आपूर्ति के लिए वे आरडीपीएल को समय पर आदेश प्रेषित करे।

उपभोक्ता संघ के प्रबन्ध संचालक श्री आर.एस. जाखड़ ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा दवा लिखने पर ही जनोषधि केन्द्र सफल हो सकते हैं।

आरडीपीएल के प्रबन्ध संचालक श्री एम.के. नागेन्द्र ने बताया कि 15 जुलाई तक 130, इस माह के अंत तक 160 और दो माह में सभी 550 दवाओं की आपूर्ति जनोषधि केन्द्रों पर सुनिश्चित कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है जिससे दवाओं की मांग व आपूर्ति की समीक्षा हो सके।

बैठक में उप सचिव सहकारिता श्री महेश गुप्ता, उपसचिव चिकित्सा शिक्षा श्रीमती छाया भटनागर, निदेशक आर.एन.डी पुरोहित, अतिरिक्त निदेशक पी. आर. मीणा, जयपुरिया अस्पताल की प्रभारी एन.के. वशिष्ठ, कांवटिया प्रभारी एस.के. गुप्ता, महा प्रबन्धक उपभोक्ता संघ मुकुन्द सिंह उपस्थित थे।

जून-जुलाई में उपहार सहकार स्टेशनरी मेले

जयपुर में नवजीवन सहकारी बाजार में लगा स्टेशनरी मेला

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने उपभोक्ता संघ सहित सभी सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को निर्देश दिए है कि स्कूली बच्चों की शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपहार स्टेशनरी मेले आयोजित किए जाएं।

श्री शर्मा ने बताया कि नवजीवन बाजार पर आयोजित उपहार सहकार स्टेशनरी मेले में रियायती दर पर विभिन्न साइज की अभ्यास पुस्तिकाएं, स्कूल बैग्स, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, पेन, पेंसिल, शॉपनर, ड्रॉईंग बॉक्स,ज्यॉमिट्री बॉक्स, कलर, इरेजर, बच्चों के रेनकोट, छाते आदि उपलब्ध कराए गए।

सहकारिता आंदोलन के मर्म को आम जनता व नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि **'एक सब के लिए और सब एक के लिए'** की भावना को लेकर जो सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था, उसके मर्म को आम जनता और नई पीढ़ी को समझाएंगे, तभी यह आगे बढ़ेगा।

श्री गहलोत जयपुर के भगवान दास रोड पर राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की नवनिर्मित एवं कम्प्यूटरीकृत सी-स्कीम शाखा के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरु के जमाने से सहकारिता आंदोलन का पंचवर्षीय योजना में स्थान रहा है, लेकिन 30-40 साल पहले जो इसमें ठहराव आया, इसके बाद जिस रूप में इसे आगे बढ़ना चाहिये था, यह आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडू जैसे राज्यों की तरह मजबूत नहीं बन पाया। दूसरे राज्यों की तरह यहां भी आगे बढ़ाने के लिए इसे जनता का आंदोलन बनाना होगा, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

श्री गहलोत ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को पूरे देश में तथा विशेषकर राजस्थान जैसे प्रदेश में मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के इस दौर में एक बड़ा संदेश जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षित युवा सरकारी नौकरियों की तरफ देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने से जीवन भर के लिए सुख हो जाएगा। नौकरी हासिल करने के बाद वे निश्चिंत हो जाते हैं। इस भावना से उनका व्यक्तित्व एवं उनमें छिपी प्रतिभा दबी रह जाती है, उनकी उद्यमिता भी सामने नहीं आ पाती। उनमें जो प्रतिभा छिपी है उसका लाभ देश-प्रदेश को व मानव संसाधन को तभी मिल पाएगा, जब वे अपनी उद्यमिता के बल पर अलग से कुछ कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें कुछ नया कर दिखाने के प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि कोई बैंक पांच साल पहले बंद हो गई हो और वह फिर से शुरु हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात उस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस बैंक का सुदृढ़ होना समाज के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए व सहकारिता के लिए जरूरी है, ताकि यह उदाहरण बन सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैंक में उपलब्ध कम्प्यूटराइजेशन एवं कोर बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। उन्होंने बैंक के पुनः शुरु होने पर संचालक मण्डल के सदस्यों को बधाई दी।

कार्यक्र म में केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने कहा कि हमें प्रयास करने होंगे कि सहकारिता फिर से एक आंदोलन का रूप ले, ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बैंक को फिर से शुरु कर इससे जुड़े लोगों में उम्मीद की नई किरण जगाने के लिए संचालक मंडल को बधाई दी।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री महादेव सिंह खंडेला ने कहा कि बैंक ने फिर से शुरुआत कर खातेदारों का विश्वास जीता है।

कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की प्रगतिशील सोच की वजह से पांच साल पहले बंद हुआ यह बैंक फिर से शुरु हो पाया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधिवत मंत्रोच्चार के बीच फीता खोलकर बैंक का उद्घाटन किया। श्री गहलोत व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन भी किया। बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष श्री अजय चौपड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बैंक परिसर का अवलोकन कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने एटीएम कार्ड के प्रतिरुप का भी लोकार्पण किया।

स्वामी, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी, राजस्थान, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री मुकेश शर्मा द्वारा नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर से प्रकाशित एवं मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड़, जी-1/138, इंडस्ट्रियल एरिया मालवीय नगर, जयपुर से मुद्रित ● संपादक : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा।